पेज थ्री देहरादून

हमारा दून

देहरादून मंगलवार 15 सितंबर 2020

किसान विरोधी अध्यादेशों की प्रतियां फूंकते हुए विभिन्न राजनैतिक दल।

बच्चों के मेंटल हेल्थ पर फोकस करना होगा

एग्रो प्रोसेसिंग एवं फोरेस्टरी सेक्टर में अनेक कार्य किये जा सकते हैं। विनीत नायर ने कहा कि मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में अनेक कार्य हो सकते हैं। हमें सबसे पहले बच्चों के मेंटल हेल्थ पर फोकस करना होगा। रमन रॉय ने कहा कि लाईवलीहुड बिजनेस पर ध्यान देने की जरूरत है। राज्य बिजनेस के कल्चर को प्रमोट करने की जरूरत है। विभिन्न सेक्टर में कार्य करने के लिए प्रत्येक सेक्टर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने होंगे। संजीव बिखचंदानी ने कहा कि राज्य में कुछ बड़े उद्योग स्थापित करने होंगे।

उत्तराखण्ड में कृषि की संभावनाएं सीमित हैं

सीएम स्वरोजगार योजना में सोलर पॉवर फार्मिंग को भी शामिल किया गया है। मेडिकल के क्षेत्र में अनेक कार्य हो सकते हैं, आयुष, वैलनेस, मेडिसनल प्लांट के क्षेत्र में काफी कार्य हो सकते हैं। हेल्थ केयर के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के साथ रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए '13 डिस्ट्रिक्ट, 13 न्यू डेस्टिनेशन' पर कार्य किया जा रहा है। राज्य में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य हो सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में कृषि की संभावनाएं सीमित हैं। नगरीय विकास से सेवा क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं।

सचिवालय में आयोजित की गई 'मुख्यमंत्री सलाहकार समूह' की पहली बैठक

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाये गये समूह में 13 सदस्य

निर्देश

■ शंकराचार्य समाधि का कार्य 31 दिसंबर तक हर हाल में ही पूर्ण

■ तीर्थ पुरोहितों हेतु भवनों को शीघ्र पूर्ण कर जिला प्रशासन को सौंपा जाए

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में 'मुख्यमंत्री सलाहकार समूह' की प्रथम बैठक आयोजित की गई। राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखण्ड सरकार ने ''स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता पर मुख्यमंत्री सलाहकार समूह'' स्थापित किया है। राज्य में स्टार्टअप ईकोसिस्टम विकसित करने के लिए इस समूह द्वारा नवाचार और उद्यमिता के लिए राज्य में एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने, अनुसंधान और नये उत्पादों, सेवाओं, व्यापार मॉडल के विकास को प्रोत्साहित करने, उपयुक्त पॉलिसी योजनाओं और आवश्यक समर्थन प्रणाली को विकसित करने हेतु परामर्श देना है।

इसके अलावा पाठ्यक्रम, मॉड्यूल प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में नवाचार और उद्यमशीलता के बारे में जागरूकता, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निकायों और एजेंसियों के साथ आवश्यक साझेदारी हेतु सलाह देना है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बनाये गये 'मुख्यमंत्री सलाहकार समूह' में 07 सरकारी एवं 06 गैर सरकारी सदस्य शामिल हैं। सरकारी सदस्यों में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव उद्योग, सचिव वित्त, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी, सचिव मुख्यमंत्री, महानिदेशक उद्योग, एवं निदेशक उद्योग शामिल हैं। जबकि गैर सरकारी सदस्यों में इंडियन एंजल नेटवर्क के फाउण्डर डॉ. सौरभ श्रीवास्तव, सम्पर्क फाउण्डेशन के फाउण्डर विनीत नायर, क्वात्रो ग्लोबल सर्विस के चौयरमेन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर रमन रॉय, फार्मर ग्रुप जनरल मैनेजर एण्ड कन्ट्री हेड एच.एस.बी.सी, इंडिया श्रीमती नैना लाल किदवई, इन्फो एज के वाइस चौयरमेन संजीव बिखचंदानी एवं सन मोबिलिटी प्रा. लि. के वाइस चौयरमेन चेतन मणि शामिल है।

उद्यमिता, नवाचार एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य में यह नई पहलः मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लोकल के लिए वोकल बनने की जो बात कही गई यह उस दिशा में प्रयास है। उद्यमिता, नवाचार एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य में यह नई पहल की जा रही है।

राज्य में उद्यमिता के विकास के लिए विशेषज्ञों की राय महत्वपूर्ण

मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं। 20 सालों में राज्य ने आर्थिक गतिविधियों में काफी उन्नति की है। उद्यमियों के लिए राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। राज्य में बड़े उद्योगों पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना काल में साढ़े चार लाख से अधिक प्रवासी वापस उत्तराखण्ड आये हैं। उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। उत्तराखण्ड में साक्षरता दर काफी अच्छी है। इसके लिए विशेषज्ञों की राय काफी महत्वपूर्ण होगी। राज्य में सीएम इनोवेशन फण्ड बनाया गया है।

जिसमें सरकारी के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के गैर सरकारी विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इन विशेषज्ञों की सलाह से राज्य के औद्योगिक विकास एवं हिमालयी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड विविध जैव विविधताओं वाला राज्य है, यहां कि जैव विविधता का फायदा लेते हुए इस दिशा में अनेक कार्य हो सकते हैं।

संक्षिप्त समाचार

आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर के निधन पर सीएम ने जताया शोक

संवाददाता देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने डोकलाम में तैनात आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर, किच्छा निवासी जमीर अहमद के हृदयघात से निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिवार जनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।

वादकारी अपना प्रतिउत्तर डाक/ई–मेल/फैक्स द्वारा भेज सकते है

संवाददातां देहरादनू। कोविड–19 के अत्यधिक बढ़ते हुए प्रकोप के दृष्टिगत उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग में पूर्व से निर्धारित प्रतिवादों की सुनवाई हेतु दिनांक 15 सितम्बर, 2020 से अग्रिम आदेशों तक वादकारियों को व्यक्तिगत रूप से आयोग कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नही है। वादकारी अपना प्रतिउत्तर डाक/ई–मेल/फैक्स द्वारा भेज सकते हैं। यह जानकारी प्रशासनिक अधिकारी, उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग हरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा दी गई।

अब 19 तक होंगें खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन

संवाददातां देहरादून। पर्वतीय क्रिकेट एसोसिएशन चमोली के जिला सचिव नरेन्द्र शाह ने बताया है कि खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन अब 19 सितंबर तक होंगे। उन्होंने कहा कि अपना पूरे कागजात के साथ पवन भंडारी से सम्पर्क कर सकते है।

सरकार व पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश

जवाब

■ पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

देहरादून। **संवाददाता**

उच्च न्यायालय में पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास–भत्ता व अन्य देयकों की वसूली के आदेश का अनुपालन करने को लेकर रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र (रुलक) देहरादून की अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने सरकार व पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अवमानना याचिका की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से जबाव दाखिल करने को कहा था ।

मुख्य सचिव की ओर से 10 सितंबर को इस सम्बंध में जबाव दाखिल कर दिया गया है । जिसमें कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चन्द्र खंडूरी व विजय बहुगुणा ने आवास किराया जमा कर दिया है । जबकि पूर्व सीएम स्व नारायण दत्त तिवारी की पत्नी को भी भुगतान जमा करने का नोटिस दिया है जो अभी तक जमा नहीं हुआ है।

सरकार की ओर से पूर्व सीएम को बिजली पानी का बकाया बिल जमा करने को नोटिस दिया गया है। बिजली पानी के बिल कोश्यारी के नाम 11लाख,विजय बहुगुणा के नाम 4 लाख, खंडूरी के नाम 3.89लाख,डॉ निशंक के नाम 10.60लाख व स्व नारायण दत्त तिवारी के नाम 21. 75 लाख लंबित हैं ।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है, लिहाजा दो सप्ताह का समय दिया जाए।

पूर्व सीएम की ओर से जवाब दाखिल करने को समय मांगा गया। जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद के लिए नियत कर दी।

कई लोगों ने ली आम आदमी पार्टी की सदस्यता

संवाददाता देहरादून। राजपुर रोड़ विधान सभा के तिलक रोड़ पर एक बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता विशाल चोधरी प्रदेश महासचिव ने की तथा संचालन सीमा कशयप ने किया। बैठक में नये लोगो ने पार्टी कि विधिवत सदस्यता भी ली। इस बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने अपने–अपने विचार रखे। कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। क्षेत्रवासियों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मॉडल से काफी प्रभावित हुए। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र की जनता भविष्य में आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहती है और पार्टी मे जुड़कर पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्षेत्र की जनता बीजेपी कांग्रेस से हताश निराश है और 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहते हैं।

In a Digital World Why
To wait for a Howker
Visit Us at http://app.page3news.co.in
Supporting Devices
All Apple Touch Phones & Tablets
All Android Touch Phones & Tablets
All Window & BlackBerry Touch Phones 10+

Scan This Code
Read News
Watch News Channel

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिटर्स,74/9,आराघर,देहरादून से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड, पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०–
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।